**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**आर्थिक कार्य विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 37**

**(जिसका उत्तर मंगलवार, 11 दिसंबर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक) को दिया जाना है।)**

**आर्थिक वृद्घि दर में मंदी**

**37. डा. आर.टी. सुब्बारामी रेड्डी:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आर्थिक वृद्घि दर का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 2016 की दूसरी छमाही के बाद से आर्थिक वृद्घि दर मंदी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अर्थव्यवस्था का चहुँमुखी विकास करने के प्रयोजनार्थ वृद्घि दर को 7 प्रतिशत तक या उसके अधिक बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त राज्य मंत्री (श्री पोन्. राधाकृष्णन्)**

(क): केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार स्थिर (2011-12) बाजार मूल्यों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 2015-16 में 8.2 प्रतिशत, 2016-17 में 7.1 प्रतिशत और 2017-18 में 6.7 प्रतिशत थी।

(ख) और (ग): आर्थिक वृद्धि दर 2016-17 की प्रथम छमाही में 7.9 प्रतिशत से 2016-17 की दूसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत और 2017-18 की प्रथम छमाही में 6.0 प्रतिशत तक कम हो गई। तथापि, अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर 2017-18 की दूसरी छमाही में 7.4 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और इसके अतिरिक्त 2018-19 की प्रथम छमाही में 7.6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था समग्र वृद्धि दर विभिन्न कारकों पर निर्भर होती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ढांचागत, बाह्य और मौद्रिक कारक शामिल हैं और जीडीपी की वृद्धि दर में किसी एक विशेष कारक का पता लगाना कठिन है।

(घ): भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं इनमें अन्य बातों के साथ-साथ 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम और व्यापार सुगम करने के उपायों आदि के द्वारा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना परिवहन क्षेत्र के लिए ठोस उपाय करना जिसमें स्थानीय संयोजकता और विद्युत क्षेत्र के उपाय शामिल हैं जैसे उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), गंगा नदी पर द्वीप जलमार्ग को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टी मॉडल टर्मिनल को शुरू करना आदि। अन्य उपायों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए व्यापक नीति सुधार और वस्त्र उद्योग के लिए विशेष पैकेज शामिल हैं। माल एवं सेवा कर को लागू करने से व्यापार, व्यवसाय और संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों के मार्ग की बाधाओं को दूर करके विकास की गति में तेजी लाने का उपयुक्त अवसर उपलब्ध होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2018-19 के खरीफ और रबी की सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को अनुमोदित किया। सरकार ने बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया है। इसके द्वारा दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जानी है। शोधन अक्षमता का समयबद्ध रूप में समाधान करने के लिए शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन संहिता अधिनियमित की गई है। बजट 2018-19 में अर्थव्यवस्था को और अधिक गति प्रदान करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिसमें अन्य के साथ-साथ रेल एवं सड़क क्षेत्र को अधिक आवंटन के जरिए अवसंरचना को अधिक गति देना, 25 प्रतिशत के रूप में घटी हुई कारपोरेट कर की दर 250 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए भी लागू की गई जिससे 99 प्रतिशत तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्राप्त होने की आशा है। सरकार ने वृद्धि को बढ़ावा देने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विस्तार और सुविधा के लिए सहायता और पहुंच कार्यक्रम शुरू किया है।

**\*\*\*\*\***